अब हर ट्रेन में लगेंगे चार जनरल कोच, भीड़ से मिलेगी राहत

3,200	3,200	36	24
किमी की लंबी दूरी की ट्रेनों में बढ़ेंगे यात्री डिब्बे	मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ाए जाएंगे रैक	करोड़ अतिरिक्त सीटें होंगी उपलब्ध	डिब्बों वाले पूर्ण एलएचबी रैक में बदलने की योजना

नई दिल्ली, 9 अगस्त भारतीय रेलवे में लंबी दूरी का सफर करने वाले आम यात्रियों के लिए राहत की बड़ी खबर है. रेलवे अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत करीब 3,200 लंबी दूरी की ट्रेनों को 24 डिब्बों वाले पूर्ण एलएचबी रैक में बदलने की योजना है.

खास बात यह है कि प्रत्येक ट्रेन में कम से कम चार जनरल कोच रखे जाएंगे, जबकि छह से आठ स्लीपर कोच भी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे. अभी कई लंबी दूरी की ट्रेनों में महज दो जनरल कोच होने के कारण इनमें यात्रियों की भारी भीड़ रहती है. कई बार क्षमता से कई गुना अधिक यात्री इन डिब्बों में सफर करने को मजबूर होते हैं. रेलवे के इस फैसले से ऐसे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल डिब्बे आम यात्रियों के लिए सबसे सस्ता और आसान यात्रा विकल्प होते हैं. लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण इन डिब्बों में अक्सर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती. त्योहारों के दौरान स्थिति और गंभीर हो जाती है. दिवाली, छठ पूजा और अन्य प्रमुख त्योहारों के समय बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों से अपने घर लौटते हैं. ऐसे में जनरल कोच में अत्यधिक भीड़ के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. रेलवे की नई योजना के तहत लंबी दूरी की करीब 3,200 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इन ट्रेनों को 24 डिब्बों वाले पूर्ण एलएचबी रैक में बदलने की योजना है.

इनमें कम से कम चार जनरल कोच रखे जाने से बिना आरक्षण यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी. इसके साथ ही छह से आठ स्लीपर कोच होने से कम किराये में आरक्षित यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे. रेलवे के इस विस्तार का सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को होगा, जो नौकरी, पढ़ाई, कारोबार या अन्य कारणों से नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं. वर्तमान में सीमित जनरल और स्लीपर कोच के कारण यात्रियों को टिकट मिलने या ट्रेन में जगह बनाने में मुश्किल होती है. अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाने से भीड़ को अलग-अलग कोच में बांटा जा सकेगा और यात्रा अपेक्षाकृत सुविधाजनक हो सकेगी.

रेलवे के अनुसार, ट्रेनों में कोच बढ़ाए जाने से हर साल करीब 36 करोड़ अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो सकती हैं. इसका असर खास तौर पर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान दिखाई देगा, जब रेल यात्रियों की संख्या अचानक काफी बढ़ जाती है. अधिक जनरल कोच होने से यात्रियों को भीड़भाड़ वाले डिब्बों में यात्रा करने की मजबूरी कम होगी. इस योजना को आम यात्रियों के लिए रेलवे के बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है. खासकर कम आय वाले यात्रियों के लिए जनरल और स्लीपर कोच की उपलब्धता बढ़ना महत्वपूर्ण है.

ट्रेन छूटने से 5 मिनट पहले तक मिलेगा कंफर्म टिकट

भारतीय रेलवे की करंट बुकिंग सुविधा उन यात्रियों के लिए बेहद काम की है, जिनका अचानक यात्रा का प्लान बनता है या जिनका तत्काल टिकट कंफर्म नहीं हो पाता. इस व्यवस्था के तहत ट्रेन के रवाना होने से पहले खाली बची आरक्षित सीटों पर कंफर्म टिकट बुक किया जा सकता है. पहला रिजर्वेशन चार्ट सामान्यत: ट्रेन के प्रस्थान से करीब चार घंटे पहले तैयार होता है. इसके बाद खाली सीटों की स्थिति के आधार पर करंट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है. रेलवे के नियमों के मुताबिक दूसरा और अंतिम चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से करीब 30 मिनट से 5 मिनट पहले तक तैयार हो सकता है. इस दौरान केवल उपलब्ध खाली सीटों पर ही कंफर्म टिकट जारी किया जाता है, वेटिंग टिकट नहीं. खास बात यह है कि करंट बुकिंग में तत्काल टिकट की तरह अतिरिक्त तत्काल शुल्क नहीं देना पड़ता. यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर 'चार्ट्स वैकेंट' विकल्प के जरिए खाली सीटों की जानकारी देख सकते हैं और उपलब्ध सीट होने पर टिकट बुक कर सकते हैं.

जियो ने ग्राहकों के लिए पेश किए 84 दिन और एक साल के ओटीटी-पास

नयी दिल्ली, 09 अगस्त फिल्में, वेब सीरीज, लाइव स्पोर्ट्स और टीवी चैनल देखने वाले ग्राहकों के लिए जियो ने लंबी वैलिडिटी वाले ओटीटी-पास पेश किये हैं.

कंपनी ने 550 रुपये में 84 दिन और 2,000 रुपये में 365 दिन वाले दो नये पास की घोषणा की है. पहले से मौजूद 200 रुपये के पास की वैधता 28 दिन है. तीनों पास में हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड 5जी, 15 प्रीमियम ओटीटी ऐप और जियो टीवी पर 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल का एक्सेस मिलेगा. नये ओटीटी-पास के लिए ग्राहक के पास एक साल का सक्रिय बेस प्लान होना अनिवार्य होगा. वॉयस-ओनली प्लान इसमें शामिल नहीं हैं.

कंपनी की शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि लंबी अवधि का पास लेने पर ग्राहक की लागत भी कम होती है. उसने बताया कि पहले 200 रुपये का 28 दिन वाला पास अगर ग्राहक तीन बार लेता तो उसे 84 दिन के लिए 600 रुपये खर्च करने पड़ते, जबकि नया 84 दिन वाला पास 550 रुपये का है. सालभर के लिए पास पर अब 2,400 रुपये की बजाय मात्र 2,000 रुपये खर्च करने होंगे. डाटा भी अवधि के हिसाब से बढ़ेगा. जहां 200 रुपये के पास में 30 जीबी डाटा मिलता है, वहीं, 550 रुपये के पास में 90 जीबी और 2,000 रुपये के सालाना पास में 365 जीबी हाई-स्पीड डाटा मिलेगा. ओटीटी पैकेज में यूट्यूब प्रीमियम, जियोहॉटस्टार मोबाइल प्लस हॉलीवुड और अमेजन प्राइम शामिल हैं. ग्राहकों को 550 और 2,000 रुपये के पास में अमेजन प्राइम लाइट मेंबरशिप मिलेगी, जबकि 200 रुपये के पास में अमेजन प्राइम वीडियो मोबाइल संस्करण मिलेगा.

इसके अलावा ग्राहकों को सोनीलिव, जी5, लायंसगेट प्ले, डिस्कवरी प्लस, सनएनएक्सटी, फैनकोड, होइचोई, चौपाल, प्लैनेट मराठी, कांचा लन्नका, टाइम्सप्ले और तरंग प्लस का एक्सेस मिलेगा. जियोटीवी पर 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल भी देखे जा सकेंगे. इनमें स्टार प्लस एचडी, कलर्स एचडी, सेट एचडी, सन टीवी एचडी, डिस्कवरी और कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल शामिल हैं.

एफपीआई ने अगस्त में किया 12,291 करोड़ निवेश

मुंबई. अगस्त विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अगस्त के पहले सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार में 12,291 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया. यह लगातार तीसरा महीना है जब एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार में लिवाल रहे हैं. उन्होंने जुलाई में 40,031 करोड़ रुपये और जून में 4,669 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था. शुद्ध निवेश बाजार में लगायी गयी पूंजी और निकाली गयी पूंजी का अंतर है.एफपीआई के अगस्त में अबतक किये गये निवेश में पूरा योगदान इक्विटी सेक्टर का रहा है. उन्होंने गत सप्ताह इक्विटी में अपना निवेश 12,921 करोड़ रुपये बढ़ाया.

ऑस्ट्रेलिया पहुंचा मिथिला मखाना किसानों को मिला बड़ा फायदा

नई दिल्ली, 9 अगस्त बिहार के प्रसिद्ध जीआई टैग वाले मिथिला मखाना ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को बताया कि पहली बार बिहार से 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना समुद्री मार्ग के जरिए ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया है.

यह निर्यात कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से हुआ. खास बात यह है कि निर्यात के लिए मखाना सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदा गया, जिससे उन्हें स्थानीय बाजार भाव की तुलना में करीब 18 प्रतिशत अधिक कीमत मिली. इससे किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं.

हर महीने चाहिए 25 हजार पेंशन, कितना चाहिए फंड

75 लाख का कॉर्पस जरूरी

30 साल बाद लक्ष्य कई गुना बढ़ेगा

नई दिल्ली, 9 अगस्त रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय रकम की जरूरत लगभग हर नौकरीपेशा व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता होती है. अगर आपका लक्ष्य रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 यानी सालाना 3 लाख की नियमित आय हासिल करना है, तो इसके लिए अभी से रिटायरमेंट फंड की योजना बनाना जरूरी है.

वित्तीय योजना में इस्तेमाल होने वाले 4% नियम के अनुसार, रिटायरमेंट के समय आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए कि उसका करीब 4% पहले साल निकाला जा सके और बाद में निकासी को महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जा सके. इस हिसाब से 3 लाख सालाना आय के लिए करीब 75 लाख का रिटायरमेंट कॉर्पस बनता है. हालांकि यह गणना आज की जरूरत के आधार पर है. अगर रिटायरमेंट में अभी 20-30 साल बाकी हैं, तो महंगाई के कारण 25,000 की मौजूदा क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए काफी बड़ा फंड चाहिए होगा. उदाहरण के तौर पर 30 साल बाद 6% औसत महंगाई दर पर आज के 25,000 की जरूरत करीब 1.43 लाख प्रति माह के बराबर हो सकती है. ऐसे में अनुमानित रिटायरमेंट फंड करीब 3.5 करोड़ से 4 करोड़ तक पहुंच सकता है. इसलिए जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाए, उतना फायदा कंपाउंडिंग का मिलता है रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि आज कितनी पेंशन चाहिए. आपकी उम्र, रिटायरमेंट की उम्र, जीवन प्रत्याशा, महंगाई और निवेश से मिलने वाला संभावित रिटर्न भी गणना को प्रभावित करते हैं. यही वजह है कि युवा उम्र में रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू करना अधिक फायदेमंद माना जाता है.

> यदि कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में है और 60 साल में रिटायर होना चाहता है, तो 6% औसत महंगाई दर मानने पर आज के 25,000 की जरूरत 30 साल बाद करीब 1.43 लाख मासिक हो सकती है. ऐसे लक्ष्य के लिए करीब 3 .5 करोड़ से 4 करोड़ का कॉर्पस जरूरी हो सकता है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एसआईपी एक विकल्प हो सकता है. 12% औसत वार्षिक रिटर्न का अनुमान मानें तो 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करने वाले व्यक्ति को 35 साल की अवधि में करीब 75 लाख से 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए लगभग 1,200-1,500 मासिक से शुरुआत करनी पड़ सकती है.

शेयर बाजारों पर आयात शुल्क का असर

मुंबई, 9 अगस्त बीते सप्ताह रही तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में घरेलू शेयर बाजारों पर अमेरिकी आयात शुल्क से संबंधित विधेयक का असर दिखेगा.

अमेरिकी संसद की सिनेट में भारत समेत पांच देशों पर रूस और ईरान से तेल खरीदने के लिए 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है. इससे सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा सकती है. इसके अलावा, बाजार पर महंगाई के आंकडों का असर भी दिखेगा. खुदरा महंगाई और थोक महंगाई के आंकड़े इसी सप्ताह जारी होने हैं.पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स तीन दिन बढ़त में और दो दिन गिरावट में रहा. सप्ताह के दौरान सूचकांक 404.53 अंक (0.52 प्रतिशत) चढ़कर 78,499.17 अंक पर बंद हुआ.निफ्टी-50 सूचकांक 187.05 अंक यानी 0.77 प्रतिशत की साप्ताहिक तेजी में 24,570.65 अंक पर पहुंच गया.

> सेंसेक्स की 30 में से 15 कंपनियों में तेजी रही. सप्ताह के दौरान भारतीय स्टेट बैंक का शेयर 6.74 प्रतिशत चढ़ा. इटरनल में 4.33 प्रतिशत, इंफोसिस में 3.81, टीसीएस में 3.72, बीईएल में 3.69, इंडिगो में 3.37 और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.09 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. एलएंडटी का शेयर 2.70 फीसदी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1.85, आईटीसी का 1.62, टाइटन का 1.39, अल्ट्राटेक सीमेंट का 1.14, एक्सिस बैंक का 0.69, कोटक महिंद्रा बैंक का 0.46 और एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 0.18 प्रतिशत मजबूत हुआ.

आधार ऐप से घर बैठे बुक करें सेवा केंद्र का अपॉइंटमेंट

नई दिल्ली, 9 अगस्त आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी अपडेट कराने के लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता है. ऐसे में केंद्रों पर लगने वाली लंबी कतार से बचने के लिए अब घर बैठे पहले से अपॉइंटमेंट बुक की जा सकती है.

नए आधार ऐप में आधार सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा दी गई है. इसके लिए उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल में आधार ऐप खोलकर 6 अंकों के पिन या बायोमेट्रिक की मदद से प्रवेश करना होगा. इसके बाद सेवा वाले विकल्प में जाकर अपॉइंटमेंट बुक करने का विकल्प चुनना होगा. आगे आधार पोर्टल पर मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए प्रवेश और ओटीपी सत्यापन करना होगा. इसके बाद नजदीकी आधार सेवा केंद्र को पिन कोड के माध्यम से खोजकर अपनी पसंद का केंद्र, तारीख और उपलब्ध समय चुन सकते हैं.

पांच कंपनियों के आईपीओ से जुटेंगे 7,443 करोड़

■ 10 से 12 अगस्त के बीच खुलेंगे सार्वजनिक निर्गम ■ मिल्की मिस्ट का होगा सबसे बड़ा दुग्ध आईपीओ

नई दिल्ली, 9 अगस्त भारतीय शेयर बाजार के प्राथमिक बाजार में अगले सप्ताह जबरदस्त हलचल रहने वाली है. धूत ट्रांसमिशन, मोलबायो डायग्नोस्टिक्स, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स, शिपरॉकेट और बिहारी लाल इंजीनियरिंग अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ लेकर आ रही हैं.

पांचों कंपनियां मिलकर बाजार से करीब 7,443 करोड़ जुटाने की तैयारी में हैं. धूत ट्रांसमिशन और मोलबायो डायग्नोस्टिक्स का सार्वजनिक निर्गम 10 अगस्त, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स का 11 अगस्त, जबकि शिपरॉकेट और बिहारी लाल इंजीनियरिंग के निर्गम 12 अगस्त को खुलेंगे. इनमें मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स का 1,553 करोड़ का निर्गम भारतीय दुग्ध क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम होगा. वहीं, मोलबायो डायग्नोस्टिक्स में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम सहित बड़े संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है. कंपनियां निर्गम से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार, नई परियोजनाओं पर खर्च, कर्ज चुकाने और अन्य कारोबारी जरूरतों के लिए करेंगी. इन पांच निर्गमों के कारण अगले सप्ताह प्राथमिक बाजार में निवेशकों की गतिविधियां काफी बढ़ने की उम्मीद है.

समाचार विशेष

बिहार की राजनीति में खुला नया विकल्प

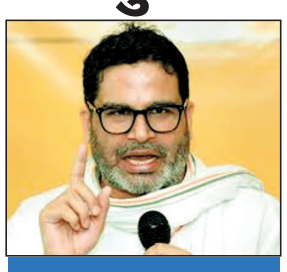

क्या बांकीपुर से प्रशांत किशोर की जीत एनडीए-आरजेडी के लिए संदेश?

पटना, 9 अगस्त. बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने राज्य में नई राजनीति और नए विकल्प की खिड़की खोल दी है. इस नतीजे ने जहां सत्तारूढ़ राजग और विपक्षी महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजाई है, वहीं मुख्यधारा के दलों को युवाओं की आकांक्षाओं को लेकर सचेत होने का संदेश भी दिया है.

नतीजे बताते हैं कि इस चुनाव में न सिर्फ राजग का अगड़ा-अति पिछड़ा बल्कि राजद का मुस्लिम-यादव समीकरण भी औंधे मुंह गिरा है. यहां तक कि भाजपा उम्मीदवार अपने बूथ पर भी पीछे रहा. इस नतीजे के कई गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं. महज एक वर्ष पूर्व जिस जनसुराज पार्टी के 238 में से 236 उम्मीदवारों ने जमानत गंवा दी थी, उसी पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में भाजपा को उसके सबसे मजबूत गढ़ में पटखनी दी है. भाजपा उम्मीदवार का आधार स्वजातीय कायस्थ और दूसरे अगड़े वर्ग के कुछ हिस्से तक ही सीमित रह गया. वहीं राजद के वोट बैंक में आई 30 हजार वोटों की कमी बताता है कि उसके मूल यादव-मुस्लिम मतदाता (22 फीसदी) ने इस बार उससे दूरी बरत ली. बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे ने बीते दो दशक से भी अधिक समय से चली आ रही राजग बनाम राजद केंद्रित राजनीति के लिए भी खतरे की घंटी बजाई है.

1988 का इलाहाबाद लोकसभा उपचुनाव ऐतिहासिक है. वीपी सिंह ने कांग्रेस के सुनील शास्त्री को भारी अंतर से हराया.

उपचुनावों ने कई बार बड़े बदलावों में भूमिका निभाई

1993 में वैशाली सीट पर जनता दल के सांसद शिवशरण सिंह के निधन के बाद हुआ उपचुनाव बिहार की राजनीति का बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ था. इसमें बिहार पीपुल्स पार्टी की लवली आनंद ने सत्ताधारी जनता दल की किशोरी सिन्हा को पटखनी दी. जीत से उत्साहित आनंद मोहन ने 1995 के विधानसभा चुनाव में 259 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए. इससे सत्ता विरोधी वोट बंटे, जिसका सीधा लाभ लालू प्रसाद और जनता दल को मिला और उनकी सत्ता में वापस आसान हो गई.

उत्तर प्रदेश में बिछने लगी सियासी बिसात

सपा वोट में सेंध की तैयारी, आजाद देंगे अखिलेश को मात

लखनऊ, 9 अगस्त. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी बिसात बिछने लगी है. एक ओर राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलने का मौका मिल गया है. तो वहीं दूसरी ओर मायावती ने भी अपनी पार्टी से गैरजिम्मेदार नेताओं को हटाना शुरू कर दिया है.

इस चुनावी रण में चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी अपनी साख जमानी शुरू कर दी है. इस बार उनकी नजर अखिलेश के वोट बैंक को कम करने की नजर आ रही है. इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने

भी इस चुनावी रण का गणित अभी से साफ कर दिया है. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए नई राजनीतिक चुनौती खड़ी करने की कोशिश की है. पार्टी ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और सिख समाज के नेताओं को मैदान में उतारकर पीडीए के समानांतर सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास किया है. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, 45 घोषित उम्मीदवारों में 18 अनुसूचित जाति (एससी), 16 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 10 मुस्लिम और एक सिख समुदाय से हैं. पार्टी ने लखनऊ छावनी, गोविंद नगर, विश्वनाथगंज सहित पांच सामान्य सीटों पर भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे हैं.

पीडीए फॉर्मूले से मेल खाती रणनीति

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि लाल कहते हैं कि जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, वहां के सामाजिक समीकरण समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले से मेल खाते हैं. दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय पर फोकस बताता है कि चंद्रशेखर अब बसपा से ज्यादा सपा के वोट बैंक में राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहते हैं. हालांकि, उनका कहना है कि फिलहाल आजाद समाज पार्टी का संगठन और चुनावी ढांचा इतना मजबूत नहीं है कि वह बड़े पैमाने पर सपा को चुनावी नुकसान पहुंचा सके.

पुराना वर्चस्व कायम करने के लिए उतरेंगे बृजभूषण

2027 के यूपी चुनाव पर टिकीं सबकी नजरें

गोंडा, 9 अगस्त. कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के महिला पहलवानों के कथित उत्पीड़न के मामले में बाइज्जत बरी होने के बाद राजनीति में नई भूमिका को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है, ऐसे में अब वह आरोपों का ग्रहण हटने के बाद राजनीतिक करियर में अपना पंख और फैलाएंगे.

यह साफ है कि बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के आगामी राजनीतिक अखाड़े में अपने पंख फैलाने और अपना पुराना वर्चस्व दोबारा स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. भाजपा में नई भूमिका के अलावा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका कोई नया दांव भी देखने को मिल सकता है. साढ़े तीन वर्ष पहले बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद होने के साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे. महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद ही उनकी राजनीतिक यात्रा पर ब्रेक लग गया था. वह छह बार सांसद रह चुके हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनकी जगह छोटे बेटे करन भूषण सिंह को टिकट दिया.

इस चुनाव में बेटे के जीत के साथ उसके पहली बार संसद पहुंचने की खुशी तो थी, लेकिन उन्हें राजनीति से जबरन रिटायर करने का मलाल भी था. पूर्व सांसद सार्वजनिक रूप से खुले मंच पर यह बात कह चुके हैं कि वह रिटायर नहीं हुए हैं बल्कि, उन्हें जबरन रिटायर किया गया है. उन्होंने यह भी दावा किया था कि 2029 का लोकसभा चुनाव वह जरूर लड़ेंगे. परदे के पीछे से तो वह अपनी राजनीतिक विरासत संभाल रहे थे लेकिन, उनकी पार्टी में कोई भूमिका तय नहीं थी.

नई भूमिका को लेकर कयासबाजी...

साढ़े तीन वर्ष के भीतर पहले ही वह अपने बेबाक बोल के कारण चर्चा का केंद्र रहे हों, लेकिन राजनीति की मुख्य धारा में उनकी गैर मौजूदगी समर्थकों को अखर रही थी. उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार समेत अन्य राज्यों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया और अपने आपको व्यस्त रखा. न्यायालय से पूर्व सांसद के बरी होने के बाद अब राजनीति में उनकी नई भूमिका को लेकर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है. अवध के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी पूर्व सांसद के समर्थकों संख्या अच्छी है.

उपयोग | विरोधी दलों की राजनीतिक जंग में उनके नाम का अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल

राजनीति से तौबा फिर भी केंद्र में तृषा कृष्णन

चेन्नई, 9 अगस्त. दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री तृषा कृष्णन ने खुद को हमेशा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और किसी भी दल की सदस्यता से पूरी तरह दूर रखा हैए लेकिन इसके बावजूद वह लगातार तमिलनाडु की राजनीति और सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

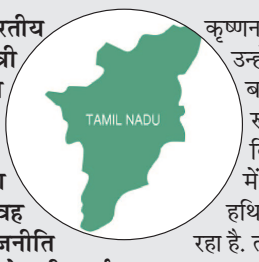

हालिया दिनों में द्रमुक के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद तृषा का नाम एक बार फिर राज्य के सबसे बड़े सियासी बवंडर के केंद्र में आ गया है. तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा और सियासत का रिश्ता दशकों पुराना है, मगर तृषा कृष्णन का मामला बिल्कुल अलग है. उन्होंने न तो कोई राजनीतिक दल बनाया है और न ही कभी सक्रिय रूप से वोट मांगे हैं फिर भी विरोधी दलों की राजनीतिक जंग में उनका नाम एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. तमिलनाडु की राजनीति में ताजा भूचाल उस समय आया जब तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक राजनीतिक रैली के दौरान विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन पर अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर बेहद आपत्तिजनक और डबल मीनिंग टिप्पणी करने का संगीन आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने उन पर छह गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

सिनेमाई जोड़ी जो बनी राजनीतिक हमलों का केंद्र

तृषा कृष्णन के राजनीति में घसीटे जाने की सबसे बड़ी वजह सुपरस्टार और मुख्यमंत्री थलापति विजय के साथ उनका लंबा और बेहद सफल करियर है. विजय और तृषा ने तमिल सिनेमा इतिहास की कुछ सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया है. बड़े पर्दे पर उनकी ऑन.स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों का अगाध प्यार मिला है, लेकिन यही लोकप्रियता अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए कीचड़ उछालने का जरिया बन चुकी है. राजनीति के दलदल में घसीटे जाने के बाद तृषा कृष्णन ने अपने कानूनी सलाहकार नित्याश नटराज के माध्यम से एक बेहद सख्त और स्पष्ट आधिकारिक बयान जारी किया है. तृषा ने अपने संदेश में साफ किया है. वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं हैं और न ही भविष्य में किसी दल में शामिल होने की उनकी कोई योजना है.